

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.*122
TO BE ANSWERED ON 11.03.2025

Addressing inflation, income stagnation and economic inequality

***122. SHRI VIVEK K. TANKHA:**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether, despite economic growth, the costs of essential goods and services have continued to rise, with inflation above 6 per cent during the last three years, if so, how Government will address the burden on lower-income households;
- (b) the reasons as to why there is no relief for middle and lower-income groups to offset the impact of GST on essential goods and the steps being taken to ease their financial strain;
- (c) the measures contemplated to boost real income growth and purchasing power, in view of the wages growing at 2.8 per cent annually since recent past; and
- (d) the plan of Government to ensure a fair tax system that supports working and middleclass populations?

ANSWER

THE FINANCE MINISTER
(SMT NIRMALA SITHARAMAN)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.122 RAISED BY SHRI VIVEK K. TANKHA FOR 11th MARCH, 2025 ON “ADDRESSING INFLATION, INCOME STAGNATION AND ECONOMIC INEQUALITY”

(a) The retail inflation averaged 5.6 per cent during the three years, from 2022-23 to 2024-25 (April-January), which is below the notified upper range of the inflation target of 6 per cent. During 2024-25 (April-January), retail inflation averaged 4.9 per cent. The core inflation that captures inflation in a variety of household goods (non-food, non-fuel) and services remained below 4 per cent for 14 consecutive months till January 2025 and averaged only 4.6 per cent during the three years, from 2022-23 to 2024-25 (April-January). Prices of certain food items have been intermittently affected by crop losses and supply chain constraints on account of adverse weather conditions.

The Government is undertaking various measures to keep the prices of essential food items in check to make them more affordable to the common man and lower-income households. These measures include building buffers of key food items, periodically releasing these items into the open market, adopting trade policies to enhance domestic food availability, preventing hoarding by setting and revising stock limits, distributing select food items like rice, wheat flour, chana, masur dal and moong dal at subsidised prices through designated retail outlets under the Bharat brand and periodic reduction in the retail selling prices of domestic LPG. To ensure food security to the poor, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana provides free food grains to more than 81 crore beneficiaries. The focused proposals in the Union Budget 2025-26, including the six-year mission for Aatmanirbharta in pulses, and, the Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana implemented in partnership with states, covering 100 districts, are likely to mitigate price pressures in food.

(b) The Government has proposed significant measures in the Union Budget 2025-26 to enhance the spending power of the middle class. The Union Budget has proposed that there will be no income tax payable upto income of ₹12 lakh per annum under the new tax regime. The Budget has also proposed a change in slabs and rates of personal income tax across the board to benefit taxpayers. The new structure is expected to substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands. The other measures of the Government to benefit the middle class include enhanced pension schemes, support for affordable housing, public health schemes and financial support to entrepreneurs.

(c) The primary policy objective of the Government is inclusive growth, which is reflected in a commitment to reduce poverty and inequality, provide social security, income generation and livelihood options, and improve the quality of life of the vulnerable sections. In order to expand job opportunities and generate incomes, the Government is implementing various employment generation initiatives such as Prime Minister's Employment Generation Programme, Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana, Rural Self Employment and Training Institutes, Standup India, Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission, Aajeevika-National Rural Livelihoods Mission, Pradhan Mantri Mudra Yojana, Production Linked Incentives, National Apprenticeship Promotion Scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and Startup India. The government is implementing the Skill India Mission to deliver skill, re-skill and up-skill training through an extensive network of skill development centres, schools, colleges, institutes, etc., under various schemes. Besides, the focus on growth-promoting measures like robust capital expenditure, continuing improvements in logistic facilities, urban development, promotion of MSMEs, agriculture and manufacturing are likely to promote overall economic growth, thereby improving employment and purchasing power of the people.

(d) The significant reforms proposed in personal income tax under the Union Budget 2025-26 are likely to boost the savings and consumption of the working and middle-class population. The GST rates on a number of items have been suitably changed from time to time by the GST Council to provide relief to consumers.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *122

(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

मुद्रास्फीति, आय में स्थिरता और आर्थिक असमानता से निपटना

*122. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान, आर्थिक वृद्धि के बावजूद, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की लागत में निरंतर वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से अधिक रही है, यदि हां, तो सरकार निम्न आय वाले परिवारों पर पड़ने वाले बोझ को किस प्रकार कम करेगी;

(ख) आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के प्रभाव को कम करने के लिए मध्यम और निम्न आय समूहों को कोई राहत नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं और उनके वित्तीय दबाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) हाल ही में मजदूरी में 2.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से हो रही वृद्धि को देखते हुए उनकी वास्तविक आय में वृद्धि करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) कामकाजी और मध्यमवर्गीय आबादी को संबल प्रदान करने वाली एक निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“मुद्रास्फीति, आय में स्थिरता और आर्थिक असमानता से निपटना” विषय पर श्री विवेक के. तन्खा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) तक तीन वर्षों के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.6 प्रतिशत रही, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य की अधिसूचित अधिकतम सीमा से 6 प्रतिशत कम है। वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 4.9 प्रतिशत रही। विविध घरेलू वस्तुओं (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) और सेवाओं में मुद्रास्फीति को दर्शाने वाली प्रमुख मुद्रास्फीति जनवरी 2025 तक लगातार 14 महीनों के दौरान 4 प्रतिशत से नीचे रही और वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) तक तीन वर्षों के दौरान औसतन केवल 4.6 प्रतिशत रही। प्रतिकूल मौसम की दशाओं के कारण फसल के नुकसान और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं के कारण कतिपय खाद्य पदार्थों की कीमतें बीच-बीच में प्रभावित हुई हैं।

सरकार आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, ताकि आम आदमी और निम्न आय वाले परिवारों के लिए उन्हें अधिक किफायती बनाया जा सके। इन उपायों में प्रमुख खाद्य पदार्थों से संबंधित बफर तैयार करना, इन वस्तुओं को समय-समय पर खुले बाजार में जारी करना, घरेलू खाद्य उपलब्धता बढ़ाने के लिए व्यापार नीतियों को अपनाना, स्टॉक सीमा निर्धारित करके और उसमें संशोधन करके जमाखोरी को रोकना, चावल, गेहूं का आटा, चना, मसूर दाल और मूंग दाल जैसी चुनिंदा खाद्य वस्तुओं को भारत ब्रांड के तहत नामित खुदरा दुकानों के माध्यम से रियायती कीमतों पर वितरित करना और घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतों में समय-समय पर कमी करना शामिल है। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख प्रस्तावों जिनमें दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन और राज्यों के साथ साझेदारी में 100 जिलों को शामिल करते हुए लागू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल है, से खाद्य पदार्थों में मूल्य दबाव कम होने की संभावना है।

(ख) सरकार ने मध्यम वर्ग की व्यय करने की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। बजट में करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर के स्लैब और दरों में व्यापार स्तर पर बदलाव करने का भी प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आने और उनके हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के अन्य उपायों में बढी हुई पेंशन योजनाएँ, किफायती आवास के लिए सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएँ और उद्यमियों हेतु वित्तीय सहायता शामिल हैं।

(ग) सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य समावेशी विकास है, जो गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने और कमजोर वर्गों के जीवन-यापन की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और आय सृजन करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, स्टैंडअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी विभिन्न रोजगार सृजन पहलों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्किल, री-स्कील और अप-स्कील प्रशिक्षण हेतु कौशल भारत मिशन को कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, सुदृढ़ पूंजीगत व्यय, लॉजिस्टिक सुविधाओं में निरंतर सुधार, शहरी विकास, एमएसएमई का संवर्धन, कृषि और विनिर्माण जैसे को बढ़ावा देने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे लोगों की रोजगार मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति बढेगी।

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत व्यक्तिगत आयकर में प्रस्तावित महत्वपूर्ण सुधारों से कामकाजी और मध्यम वर्ग की आबादी की बचत और उपभोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा समय-समय पर कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में समुचित बदलाव किया गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI VIVEK K. TANKHA: My question relates to these indicators. What are the reasons for the sharp increase, its implication on financial stability and the measures being taken by the Government and the RBI to regulate household debts and ensure responsible lending practices?

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मुद्रास्फीति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि अगर पिछले 3 वर्षों का इन्फ्लेशन देखें, तो वह औसतन 5.6 फीसदी रहा है, जो कि बेंचमार्क 6 से कम रहा है। अगर हम 2024-25 का रिटेल इन्फ्लेशन देखें, तो वह 4.9 फीसदी रहा है। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इससे पहले जब 2004 से 2014 तक की सरकारें थीं, उस समय डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होता था और उसका एवरेज 8.1 परसेंट आता था। अभी माननीय सदस्य ने विषय रखा है कि लोगों को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि यह विषय कहीं न कहीं सांख्यिकी और श्रम मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें, तो वह 60.1 परसेंट रहा है और इस दौरान बेरोजगारी दर 3.2 परसेंट रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Vivek Tankha.
...(Interruptions)...

SHRI VIVEK K. TANKHA: Sir, my question has not been answered.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your second supplementary.

श्री विवेक के. तन्खा: सर, मैंने चार इंडिकेटर्स बताए थे और मैं चाहता था कि मंत्री जी मुझे उन चार इंडिकेटर्स पर जवाब दें। Sir, my second supplementary is this. Health, home, education and food are the four important ingredients of good life for a middle class person. What specific measures is the Ministry contemplating to reduce the current high GST rates of 18 per cent on household essentials, basic education material for children and construction material for ensuring that these rates better reflect the essential nature, particularly because inflation continues to disproportionately burden the vulnerable sections of our society?

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जीएसटी का विषय उठाया है। एक देश, एक कर की व्यवस्था से इस देश में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी प्रभावी हुआ था। अगर आप एवरेज टैक्स देखेंगे जो कि पहले 15 परसेंट आता था, अब

वह घटकर 12 परसेंट हो गया है। जीएसटी की दरें और प्रक्रियाएं तय करने का निर्णय जीएसटी काउंसिल लेती है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों के मेम्बर्स उपस्थित रहते हैं। मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर निर्णय करती हैं। माननीय सदस्य ने आवास और आम जनता की बाकी समस्याओं के बारे में भी कहा। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास के आधार पर इस देश में कार्यक्रम चलाया है। अगर आप देखें, चाहे वह मकान हो, शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, गैस का सिलेंडर हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से दवा की व्यवस्था हो, इन सुविधाओं के द्वारा भारत सरकार गरीबों की चिंता कर रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Third supplementary; Ms. Dola Sen.

MS. DOLA SEN: Sir, despite the RBI's inflation target of four per cent, the food inflation has remained consistently high, which is disproportionately impacting the lower income households who constitute more than 70 per cent of our population. Beyond the short-term interventions like duty cuts, what structural measures is the Government contemplating to ensure food price stability? Through you, Sir, I would also like the hon. Finance Minister to give us update on fully revoking the GST from medical insurance, LIC and other insurance.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put one question only.

श्री पंकज चौधरी: माननीय उपसभापति जी, मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया कि जो हमारी मुद्रा स्फीति है, अगर हाल में 2025 में देखें, तो यह 4.9 फीसदी है, जो $4 \pm 2\%$ की अधिसूचित मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर है। अगर हम देखें, तो बीच-बीच में मौसम और supply chain की बाधा के कारण कभी-कभी कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आम गरीब के ऊपर बोझ न पड़े। इस पर भी हमारी सरकार निगरानी रखती है। हम buffer stock बना कर रखते हैं। साथ में, हम व्यापार नीतियों के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। इसके साथ ही, जो स्टॉक सीमा का निर्धारण होता है कि उसकी black-marketing न हो, इस पर निगाह रखी जाती है। चावल, गेहूँ, दाल, चना, मसूर, मूँग आदि को भारत ब्रांड के माध्यम से सस्ते दामों पर लोगों के बीच उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक माननीया सदस्य ने GST का सवाल उठाया है, तो मैंने पहले बताया है कि इसका निर्णय काउंसिल करती है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। डा. फौजिया खान।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, recent reports, including the findings from the International Monetary Fund, indicate that declining unionisation and stagnating real minimum wages are key factors driving rising income inequality in many economies, including India. Studies have shown that as the bargaining power of workers diminishes, wage growth fails to keep pace with productivity leading to erosion in purchasing power. In view of the evidence that weakening union representation is a structural driver of inequality, what measures is the Government considering to reinforce collective bargaining frameworks in sectors marked by pervasive wage stagnation?

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति जी, अगर आप देखें, तो प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कहीं न कहीं हर नागरिक के लिए समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। वह सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर और skilling के अवसर प्रदान कर रही है। आजादी के 70 साल के बाद भी जिन लोगों को हाशिये पर रखा गया था, उनके सशक्तीकरण के लिए हमारी सरकार पूरा जोर दे रही है। वह इन लोगों को चाहे आवास हो, शौचालय हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, जीवन बीमा हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाओं से कहीं न कहीं लाभान्वित करने का काम कर रही है।...(व्यवधान)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I need an answer to my question. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ..(Interruptions)..

श्री पंकज चौधरी: वह इन सारे गरीबों को सुविधा देने का काम कर रही है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय मिथलेश कुमार।

श्री मिथलेश कुमार: माननीय उपसभापति महोदय, आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीया वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे देश की अधिकतर आबादी गाँवों में रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन ग्रामीण देशवासियों के विकास एवं उत्थान के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है?

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति जी, यह सत्य है कि जब से 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी बने हैं, अगर आप देखें, तो 'सबका साथ सबका विकास' का जो उनका नारा है, वह केवल नारा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको यथार्थ में उतारने का काम किया है। एक तरफ जहाँ वे देश को दिन-प्रतिदिन आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं हमारी वित्त मंत्री जी लगातार infrastructure पर बजट बढ़ाती जा रही हैं। एक तरफ जहाँ हम रोड, रेल, पोर्ट,

एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स खोल रहे हैं, वहीं अगर आप गाँवों में भी देखें, तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हम सभी गाँवों को connectivity देने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने पहले भी बताया, चाहे वह आवास हो, शौचालय हो, गैस का connection हो, हम वहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी skilling की व्यवस्था करवा कर हम उनको collateral free loan भी देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से सरकार गरीबों की भी चिंता बराबर कर रही है।